भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1611**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 10 फरवरी,2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में वृद्धि एवं भारत की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति चेन को सुदृढ़ करना

1611. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातों के मूल्य का ब्यौरा क्या है और इसमें योगदान देने वाली प्रमुख उत्पाद श्रेणियां क्या है;
(ख) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातों में विशेष रूप से कितनी तेजी आई है और इन निर्यातों में मोबाइल फोन, कलपुर्जो और सहायक उपकरणों जैसे उत्पादों का योगदान कितना है;
(ग) सरकार द्वारा शुरू किए गए कौन से प्रमुख नीतिगत उपायों, प्रोत्साहन कार्यक्रमों और उत्पादन से जुड़ी पहलों ने हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता की है;
(घ) नए संयत्रों को चालू करने सहित सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से अगले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को और बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता में कितनी कमी आने की संभावना है; और
(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्या कार्यनीतियों की योजना बनाई गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): कैलेंडर वर्ष 2025 में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 47.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें वर्ष दर वर्ष 36.6% की वृद्धि दर्ज की गई। स्मार्टफोन, पॉप्यूलेटिड,लोडेड अथवा स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मॉड्यूल में असेंबल किए गए और फोटोवोल्टाइक सेल इस वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
(ख): अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। स्मार्टफोन, मॉड्यूल में असेंबल किए गए फोटोवोल्टाइक सेल,

पर्सनल कंप्यूटर पॉप्यूलेटिड,लोडेड अथवा स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन देशों में इस वृद्धि में मुख्य योगदान देने वाले उत्पाद हैं।

(ग): निर्यात बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और रोजगार सृजित करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको-सिस्टम विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)

• इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना (एसपीईसीईएस)

• इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना

• सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम

• संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)

• सार्वजनिक अधिप्राप्त (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017

• कराधान में सुधार, जिसमें टैरिफ संरचना का युक्तिकरण, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट आदि शामिल हैं।

• लागू कानूनों/विनियमों के अध्यधीन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना ।

(घ): भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास से समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के सशक्त होने और महत्वपूर्ण घटकों पर आयात निर्भरता कम होने की प्रत्याक्षा है। सरकार ने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के परिकल्पित निवेश के साथ 10 परियोजनाओं को प्रदान किया है, जिनमें 2 फैब और 8 पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके 3-6 वर्षों में परिचालित होने की प्रत्याक्षा है।

(ङ): नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। इससे निर्यात में भी वृद्धि होगी। निर्यात की मात्रा विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे वैश्विक मांग, आपूर्ति और मूल्य रुझान, गुणवत्ता में सुधार और विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन।

*****